अगस्त 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 12 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

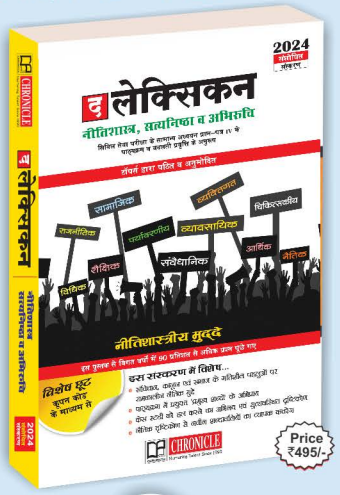

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

50 महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा टॉपिक मॉडल प्रश्नों के साथ

UPPCS प्रारंभिकी विशेष

आधुनिक भारतीय इतिहास

विशेष आलेख

- **साइबर स्पेस की सुरक्षा**
  भारत की चुनौतियां एवं अनिवार्यताएं
- **भारत-बांग्लादेश सहयोग**
  द्विपक्षीय प्रगति एवं विकास हेतु आवश्यक
- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था**
  वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं बढ़ावा देने के प्रयास
- **मेथनॉल विषाक्तता**
  प्रभाव एवं प्रबंधन के उपाय
- **भारत में बाल पोषण**
  स्थिति में सुधार हेतु संसाधनों का उचित वितरण एवं निगरानी आवश्यक
- **मादक पदार्थों की तस्करी**
  वैश्विक चुनौती के समाधान हेतु संस्थागत उपायों का नवीनीकरण आवश्यक
- **भारत का गैर-धारणीय शहरीकरण**
  चुनौतियां एवं अनिवार्यताएं

अन्य आकर्षण

न्यूज बुलेट्स
पत्रिका सार : जून 2024 में प्रकाशित पत्रिकाओं पर आधारित
चर्चित शब्दावली
संसद प्रश्नोत्तरी
समसामयिक प्रश्न
वनलाइनर करेंट अफेयर्स

अगस्त 2024 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

इस अंक में

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

अगस्त 2024

❑ वर्ष 33 ❑ अंक 12

63 सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विशेष-2
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इस विशेष खंड में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 50 महत्वपूर्ण विषयों (Topics) पर सारगर्भित एवं व्यापक सामग्री का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा इन विषयों की पहचान विगत वर्षों के प्रश्नों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के आधार पर की गई है। विषयों के केवल उन आयामों को ही शामिल किया गया है, जिनकी आगामी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। इस विशेष खंड में हम प्रत्येक विषय के पश्चात एक अति संभावित मॉडल-प्रश्न दे रहे हैं। ये प्रश्न आपको परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में मददगार होंगे।

109 UPPCS प्रारंभिकी विशेष
आधुनिक भारतीय इतिहास

सामयिक आलेख

07 साइबर स्पेस की सुरक्षा : भारत की चुनौतियां एवं अनिवार्यताएं
10 भारत का गैर-धारणीय शहरीकरण : चुनौतियां तथा अनिवार्यताएं
12 भारत-बांग्लादेश सहयोग : द्विपक्षीय प्रगति एवं विकास हेतु आवश्यक

इन फोकस

14 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था : वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं बढ़ावा देने के प्रयास
15 मेथनॉल विषाक्तता : प्रभाव एवं प्रबंधन के उपाय
16 मादक पदार्थों की तस्करी : वैश्विक चुनौती के समाधान हेतु संस्थागत उपायों का नवीनीकरण आवश्यक
17 भारत में बाल पोषण : स्थिति में सुधार हेतु संसाधनों का उचित वितरण एवं निगरानी आवश्यक

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य

राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली..... 19
न्यायपालिका..... 22
संस्थान एवं निकाय..... 23

सार्वजनिक नीति

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के नियम अधिसूचित..... 24
फेमा के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव..... 24
जम्मू कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश..... 25
अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम..... 25
दूरसंचार अधिनियम के कुछ प्रावधान प्रभावी..... 25
कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए मसौदा खनन योजना दिशानिर्देश..... 26
डाकघर अधिनियम 2023..... 26

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक..... 27
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक..... 28

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक न्याय 32
सामाजिक-आर्थिक विकास 33

कल्याणकारी योजनाएं

राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 34
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना 34
'बैंक क्लिनिक' पहल 35
ABHA-आधारित स्कैन और शेयर सेवा 35
अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान 'ई-श्रम पोर्टल' का प्रदर्शन 36
डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना का विस्तार 36
'जल जीवन मिशन' से आगे का दृष्टिकोण 36

विरासत एवं संस्कृति

ऐतिहासिक व्यक्तित्व 37
कला एवं संस्कृति 38
स्थापत्य विरासत 39

आर्थिक परिदृश्य

अवसंरचना 40
उद्योग 40
सेवा क्षेत्र, संसाधन 42
बैंकिंग एवं वित्त 43
विदेशी व्यापार और एफडीआई 45
भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएं 45

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

अंतरराष्ट्रीय संगठन 46
वैश्विक मुद्दे 48
मानचित्र के माध्यम से 49
अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते 50
अंतरराष्ट्रीय संबंध 52

पर्यावरण एवं जैव विविधता

सतत विकास 53
प्रदूषण 53
जलवायु परिवर्तन 54
आपदा प्रबंधन 56
जैव विविधता 56

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान 58
रक्षा-विज्ञान 59
स्वास्थ्य विज्ञान 60
जैव-प्रौद्योगिकी 62
नवीन प्रौद्योगिकी 62

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य परिदृश्य

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार 125
राजस्थान 126
जम्मू एवं कश्मीर 126
असम 126
तमिलनाडु 126

न्यूज बुलेट्स 127-141

लघु सूचिका

चर्चित व्यक्तित्व/ नियुक्ति 142
निधन 142
पुरस्कार एवं सम्मान 142

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व 144
क्रिकेट 144
शतरंज 144
बैडमिंटन 144
टेनिस 145
निशानेबाजी 145
टेबल टेनिस 145
एथलेटिक्स 145

पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर 146-154

चर्चित शब्दावली 155

संसद प्रश्नोत्तरी 156

समसामयिक प्रश्न 157-158

वनलाइनर करेंट अफेयर्स 159-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-1 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

साइबर स्पेस की सुरक्षा
भारत की चुनौतियां एवं अनिवार्यताएं

• संपादकीय डेस्क

वर्तमान समय में साइबर स्पेस मानव जीवन और संगठनों का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग बन गया है। यह सभी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं जैसे- विद्युत उत्पादन एवं वितरण; परिवहन; सामरिक उद्योग (Strategic Industry); वित्त; दूरसंचार तथा शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूचना निर्माण, विश्लेषण, भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति का एक प्रमुख माध्यम है। संक्षेप में, साइबर स्पेस वह ऑक्सीजन बन गया है, जिस पर वैश्विक समुदाय प्रगति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

18 जून, 2024 को भारत के चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) ने नई दिल्ली में आयोजित चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया। यह संयुक्त सिद्धांत साइबर स्पेस संचालन के सैन्य पहलुओं को समझने पर जोर देता है तथा आज के जटिल सैन्य परिचालन के वातावरण में यह साइबर स्पेस संचालन करने में सेनाध्यक्षों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

* इसके अलावा, आज के परस्पर अंतर्संबंधित विश्व में साइबर स्पेस ने समकालीन समाज में कई जटिल मुद्दों एवं बाधाओं को जन्म दिया है। इनमें से साइबर सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता के रूप में सामने आई है; विशेषत: तब, जब डिजिटल बुनियादी ढांचे पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है।

साइबर सुरक्षा: भारत की भेद्यताएं एवं चुनौतियां

अमेरिकी साइबर सुरक्षा प्रतिष्ठान 'रीसिक्योरिटी' (Resecurity) ने अक्टूबर 2023 में जारी अपनी मीडिया रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के कुछ मामलों का खुलासा किया था; रिपोर्ट के अनुसार 800 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी डार्क वेब (Dark Web) पर बेची जा रही थी।

* इसके अलावा, साइबर सुरक्षा प्रतिष्ठान के मानव खुफिया विभाग हंटर (HUNTER) ने कहा था कि साइबर हमले के अपराधी "संपूर्ण आधार कार्ड एवं भारतीय पासपोर्ट डेटाबेस को 80,000 डॉलर में बेचने को तैयार थे।"
* इससे पहले, नवंबर 2022 में नई दिल्ली में एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (AIIMS), पर भी साइबर हमला हुआ था, जिसने अस्पताल की चिकित्सा परामर्श एवं डिजिटल सेवाओं को प्रभावित किया था।
* ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना रैनसमवेयर हमले से संबंधित थी, जिसमें प्रणाली को हैक करने वाले अपराधी कथित तौर पर फिरौती की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवा उद्योग के अलावा, भारत में कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र भी साइबर हमलों का निशाना बन चुके हैं। केवल 2023 में ही, भारत में 1,12,474 साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 2023 के पूर्वार्द्ध में वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने वाली 4.29 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं शामिल हैं।

✓ चुनौतियां

भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कई तरह के खतरे और भेद्यताएं शामिल हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां अग्रलिखित हैं:

* **साइबर सुरक्षा खतरे:** डेटा उल्लंघन, रैनसमवेयर एवं फिशिंग हमलों सहित साइबर हमलों के प्रसार के साथ, साइबर सुरक्षा एक उल्लेखनीय चिंता के रूप में उभरी है। संवेदनशील जानकारी तथा बुनियादी ढांचे को दुर्भावनापूर्ण अभिकर्ताओं से बचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
* **डिजिटल विभाजन:** प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच में असमानताएं एक डिजिटल विभाजन को उत्पन्न करती हैं, जो सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अवसरों को सीमित करता है।
* इस अंतराल को पाटने के लिए साइबर स्पेस संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
* **गलत सूचना एवं दुष्प्रचार:** ऑनलाइन झूठी सूचना तथा प्रचार का तेजी से प्रसार लोकतंत्र एवं सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। गलत सूचना के प्रसार को संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, मीडिया संस्थान तथा नीति निर्माताओं के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
* **विनियामक चुनौतियां:** साइबर स्पेस की सीमाहीन प्रकृति विनियामक प्रयासों को जटिल बनाती है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनों को लागू करने में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। साइबर स्पेस को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी विनियामक ढांचे का विकास निरंतर चुनौती बना हुआ है।
* **साइबर युद्ध एवं भू-राजनीतिक तनाव:** जासूसी, संगठित हिंसा तथा युद्ध के लिए साइबर स्पेस का बढ़ता उपयोग भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाता है तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। साइबर संघर्षों का प्रबंधन करना तथा साइबर स्पेस में व्यवहार के मानदंड स्थापित करना जटिल कूटनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है।
* **उभरती प्रौद्योगिकियों की नैतिक दुविधाएं:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति स्वायत्तता, जवाबदेही एवं पूर्वाग्रह से संबंधित नैतिक दुविधाएं उत्पन्न करती है। साइबर स्पेस में 'उत्तरदायी नवाचार' (Responsible Innovation) के लिए इन नैतिक चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक है।
* **बुनियादी ढांचे का लचीलापन:** साइबर खतरों तथा प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध दूरसंचार नेटवर्क तथा पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण साइबर स्पेस बुनियादी ढांचे के लचीलेपन की कमी सामाजिक कार्य पद्धति एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक उल्लेखनीय खतरा पैदा करती है।

भारत का गैर-धारणीय शहरीकरण

चुनौतियां तथा अनिवार्यताएं

• डॉ. अमरजीत भार्गव

शहरी क्षेत्र आर्थिक विकास के इंजन हैं, जिन्हें धारणीय रूप से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। धारणीय शहरीकरण (Sustainable Urbanisation) के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने के लिए नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। बहु-स्तरीय समन्वय, सहयोग तथा जन-भागीदारी के माध्यम से न केवल शहरी प्रशासन को सशक्त किया जा सकता है बल्कि धारणीय शहरीकरण की अवधारणा को वास्तव में मूर्त रूप दिया जा सकता है।

विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत की कुल आबादी के लगभग 40% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करेंगे तथा भारत के शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% का योगदान देंगे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों से भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति तीव्र हुई है। एक तरफ जहां भारत, सतत विकास लक्ष्य-11 के अनुरूप विशेष रूप से शहरों को सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने हेतु प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी तरफ, अनियमित शहरीकरण के कारण उत्पन्न चुनौतियों तथा अव्यवस्था के कारण शहरों की गैर-धारणीयता में वृद्धि हुई है। गैर-धारणीय शहरीकरण की प्रवृत्ति समावेशी, लचीले और टिकाऊ विकास के मार्ग में प्रमुख बाधक है।

- स्वतंत्रता के 100वें वर्ष अर्थात 2047 तक विकसित देश बनने की महत्वाकांक्षा तभी साकार हो सकेगी, जब देश में तीव्र गति से हो रहे गैर-धारणीय शहरीकरण की प्रकृति को बेहतर रूप में प्रबंधित किया जा सकेगा।
  - इस संदर्भ में भारत की शहरीकरण की प्रवृत्ति, गैर-धारणीय शहरीकरण के कारण तथा धारणीय शहरीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना प्रासंगिक है।

भारत में गैर-धारणीय शहरीकरण

✓ गैर-धारणीय शहरीकरण के प्रमुख कारण

- **प्रशासनिक समस्याएं:** अधिकांश शहरी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को समय की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इसके कारण प्रशासनिक ढांचे में नियोजन कौशल का अभाव देखने को मिलता है।
- **सीमित जवाबदेही तथा गैर-पारदर्शी व्यवस्था:** शहरी नियोजन में अनेक विभाग एवं एजेंसियां शामिल हैं।
  - इससे मुद्दों की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है तथा जवाबदेही खंडित हो जाती है। यह स्थिति अंततः गैर-पारदर्शी व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है।
- **नियोजन हेतु उचित प्लानिंग का अभाव:** देश के अधिकांश शहरों का विकास एवं विस्तार उचित 'मास्टर प्लान' के अभाव में हुआ है।
  - भविष्य के संदर्भ में भी अधिकांश शहरी क्षेत्रों में भूमि के उपयोग तथा विस्तार संबंधी स्पष्ट नीति नहीं है।
- **अत्यधिक भीड़भाड़:** वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या के कारण शहरी क्षेत्रों के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव में वृद्धि तथा प्रदूषण जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं।

✓ भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति

- भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था है तथा कुल वैश्विक शहरी आबादी का लगभग 11% हिस्सा भारतीय शहरों में रहता है।
- भारतीय जनगणना के अनुसार शहरी समूहों/कस्बों की संख्या 1901 में 1827 से बढ़कर 2011 में 7935 हो गई है।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या 1901 में 2.58 करोड़ से बढ़कर 2011 में 37.71 करोड़ (कुल आबादी का 31.2%) हो गई है।
- देश की 75% से अधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल जैसे 10 राज्यों में निवास कर रही है।
- गोवा 62.2% शहरी आबादी के साथ सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है।
- नीति आयोग के अनुसार, भारतीय शहरों का विस्तार केवल 3% भूमि पर है, किंतु इनका सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% का योगदान है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय शहरी क्षेत्र में 9.3% बेरोजगारी दर्ज की गई थी।
- इसी प्रकार, वर्ल्डवाइड फंड (WWF) की एक रिपोर्ट के अनुसार तीव्र शहरीकरण के कारण वर्ष 2050 तक लगभग 30 भारतीय शहरों को गंभीर जल जोखिम का सामना करना पड़ेगा।
- विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में झुग्गियों में रहने वाली आबादी कुल शहरी आबादी का 35.2% थी।

✓ गैर-धारणीय शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियां

- **बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव:** अस्थिर भूमि की कीमतें, गैर-वहनीय किराया, किफायती स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं की कमी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याओं के कारण वर्तमान शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिल रहा है।
- **किफायती आवास की कमी:** जीवनयापन की उच्च लागत तथा किफायती आवास की कमी के कारण भारतीय शहरों की एक बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश है।
- **जल एवं स्वच्छता:** यह दोनों विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं।
  - केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य उचित समन्वय के अभाव में अपर्याप्त जलापूर्ति तथा खराब स्वच्छता से उत्पन्न समस्याओं का सर्वाधिक प्रभाव शहरी गरीब लोगों पर पड़ता है।

भारत–बांग्लादेश सहयोग

द्विपक्षीय प्रगति एवं विकास हेतु आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

भारत-बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक संबंधों की जड़ें वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में खोजी जा सकती हैं। समय के साथ दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत किया है। भूमि तथा नदी जल बंटवारे पर किए गए समझौते दोनों देशों के मध्य बेहतर सहयोग एवं समन्वय का प्रतीक हैं।

21-22 जून, 2024 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान किसी विदेशी नेता की पहली राजकीय यात्रा थी। पिछले एक दशक से दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु अथक प्रयास कर रहे हैं। संबंधों को सुधारने के लिए दोनों नेताओं की प्रतिबद्धता के उत्पादक परिणामों को भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में एक 'स्वर्णिम अध्याय' के रूप में चिह्नित किया गया है। उपर्युक्त संदर्भ में दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के साथ मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

द्विपक्षीय बैठक के मुख्य बिंदु

इस दौरान दोनों देशों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इन समझौतों में समुद्री सहयोग व ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते तथा डिजिटल भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण तथा हरित भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण के दस्तावेज से जुड़े समझौते शामिल हैं।

- **भविष्योन्मुख भागीदारी:** दोनों देशों ने परस्पर प्रगति की आवश्यकतानुरूप भविष्योन्मुख भागीदारी को 'विकसित भारत 2047' और 'स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041' के साथ संरेखित करने के महत्व को स्वीकार किया।
- **परिवर्तनकारी कनेक्टिविटी:** कनेक्टिविटी में सुधार करके दोनों देश मल्टी-मोडल परिवहन, सीमा पार व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से भौगोलिक निकटता को आर्थिक अवसरों में बदलना चाहते हैं।
- **विद्युत एवं ऊर्जा सहयोग:** नेपाल एवं भूटान के साथ सहयोग में वृद्धि करके दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा सहित अंतर-क्षेत्रीय विद्युत व्यापार का विकास हेतु सहमत हुए हैं।
- **डिजिटल एवं हरित साझेदारी:** इसके माध्यम से आर्थिक विकास, सतत विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने की वकालत की गई है।
- **व्यापार और निवेश:** दोनों देशों ने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के क्रम में 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) के लिए शीघ्र वार्ता आरंभ करने तथा बांग्लादेश में 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' (SEZs) को चालू करने पर सहमति व्यक्त की।
- **जल संसाधन प्रबंधन:** भारत और बांग्लादेश विनिमय और अंतरिम जल-साझाकरण ढांचे को तैयार करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें गंगा जल बंटवारा संधि का नवीनीकरण और तीस्ता नदी का प्रबंधन शामिल है।
- **रक्षा सहयोग:** रक्षा संबंधों को मजबूत करने के क्रम में बहुमुखी सैन्य संलग्नता को बढ़ावा देकर भारत, बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।
- **विकास सहयोग:** दोनों देश विकास सहयोग का विस्तार करते हुए सिविल सेवाओं, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस और अन्य विशिष्ट सेवाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- **सीमा पार यात्रा:** भारत, बांग्लादेशी नागरिकों को ई-मेडिकल वीजा सुविधाएं प्रदान करेगा तथा कांसुलर सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलेगा।
- **हिंद-प्रशांत सहयोग:** दोनों देश सह-नेतृत्व के माध्यम से 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' (IPOI) के तहत 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन' को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही, एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत-बांग्लादेश के मध्य सहयोग के क्षेत्र

- **ऐतिहासिक सहयोग:** वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत द्वारा महत्वपूर्ण सैन्य एवं भौतिक सहायता प्रदान की गई थी। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की पहली स्वतंत्र सरकार का गठन और प्रशासन कोलकाता के थिएटर रोड से किया गया था।
  - 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद जनरल जियाउर्रहमान (1975-1981) और जनरल एच.एम. इरशाद (1982-1991) के सैन्य शासन के दौरान सीमा विवाद, उग्रवाद और जल-बंटवारे जैसे मुद्दों पर भारत विरोधी भावना में वृद्धि देखने को मिली।
  - 1991 में संसदीय लोकतंत्र की वापसी और 1996 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी जल बंटवारे पर समझौते के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया।
- **राजनीतिक सहयोग:** भारत और बांग्लादेश ने आपस में घनिष्ठ राजनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, जिसमें अक्सर द्विपक्षीय यात्राएं और सरकार के प्रमुखों के बीच घनिष्ठ संबंध शामिल हैं।
  - **उदाहरण**- भारत द्वारा बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **भूमि सीमा समझौता (2015):** भारत और बांग्लादेश ने विवादित द्वीपों की अदला-बदली की और निवासियों को अपने निवास का देश चुनने की अनुमति दी।

in फोकस

- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था : वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं बढ़ावा देने के प्रयास
- मेथनॉल विषाक्तता : प्रभाव एवं प्रबंधन के उपाय
- मादक पदार्थों की तस्करी : वैश्विक चुनौती के समाधान हेतु संस्थागत उपायों का नवीनीकरण आवश्यक
- भारत में बाल पोषण : स्थिति में सुधार हेतु संसाधनों का उचित वितरण एवं निगरानी आवश्यक

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं बढ़ावा देने के प्रयास

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देश की हिस्सेदारी 2021 की तुलना में 2030 तक चार गुना बढ़ने का अनुमान है।

- इनके अनुसार, अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2022 में 1 से बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 200 हो गई है। यह 200 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि केवल वर्ष 2023 में, लगभग आठ महीनों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।
- 'अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था' (Space Economy) शब्द से तात्पर्य अंतरिक्ष में उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं है। OECD द्वारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की गतिविधियों की पूरीश्रृंखला और संसाधनों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अंतरिक्ष की खोज, शोध, समझ, प्रबंधन और उपयोग के दौरान मनुष्यों के लिए मूल्य एवं लाभ उत्पन्न करते हैं।

भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

- **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी:** भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं की इसे वर्ष 2030 तक 8 प्रतिशत और वर्ष 2047 तक 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके है।
- **भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार:** भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 2023 में 8.4 बिलियन डॉलर था। इसमें से डाउनस्ट्रीम सेवा बाजार (मुख्य रूप से संचार और डेटा अनुप्रयोगों से संबंधित) कुल अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 80% हिस्सा है।
- **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate-CAGR):** विभिन्न बाजार सर्वेक्षणों के अनुसार, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8% की औसत CAGR के साथ बढ़ी है। इसके साथ ही देश में अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की संख्या भी बढ़ रही है।
- **निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका:** निजी कंपनियां उपग्रह आधारित संचार समाधान, उपग्रह एकीकरण और परीक्षण सुविधाओं की खोज कर रही हैं। सैटेलाइट सबसिस्टम और ग्राउंड सिस्टम का स्थानीय विनिर्माण निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।
- **सैटेलाइट लॉन्च में वृद्धि:** इसरो द्वारा किए गए लॉन्च की संख्या में वृद्धि हुई है। 1990 के दशक से इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से, 389 (90% से अधिक) पिछले 9वर्षों में लॉन्च किए गए थे।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियां

- **बजटीय बाधाएं:** भारत में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के लिए बजट में कमी देखी गई। इससे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आकार में हो रही वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अंतरिक्ष विभाग का व्यय 2023-24 के केंद्रीय बजट में 8% घटाकर ₹12,543.91 करोड़ कर दिया गया है, जबकि पिछले बजट अनुमान में यह ₹13,700 करोड़ था।
- **डेटा की कमी:** भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न हितधारकों का उचित वैज्ञानिक तरीके से डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता है। इसके अलावा भारत में अभी तक अंतरिक्ष-आधारित रिमोट सेंसिंग उद्योग के आकार को निर्धारित नहीं किया जा सका है, केवल अनुमान ही लगाया जाता है।
- **अंतरिक्ष मलबा:** वर्तमान में अन्तरिक्ष बाजार खुला है, इसके साथ ही अधिक से अधिक देश एवं संस्थान अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इससे अंतरिक्ष मलबे की समस्या बढ़ रही है। पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित अनुपयोगी वस्तुएं अंतरिक्ष मलबे के रूप में जानी जाती हैं।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष मलबे में 1 से 10 सेमी (0.4 और 4 इंच) के बीच के लगभग 200,000 टुकड़े हैं तथा 1 सेमी से छोटे लाखों टुकड़े हो सकते हैं।
- **प्रतिभा पलायन:** भारत दुनिया के सबसे बेहतरीन मानव संसाधन का उत्पादन करता है, लेकिन उन्हें देश में बनाए रखने में असमर्थ है।
  - लोग बेहतर अवसरों और करियर की तलाश में देश से पलायन करते हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में बाधा बन सकता है।
- **मजबूत विवाद निपटान तंत्र का अभाव:** यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित करता है, उदाहरण के लिए, एंट्रिक्स-देवास सौदे को रद्द करने से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Governmental Entities- NGEs) की शुरू से अंत तक भागीदारी को सक्षम बनाती है।

राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली

- नरेन्द्र मोदी : लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री
- विशेषाधिकार समिति ने 12 सांसदों को कदाचार का दोषी पाया
- लोक सभा में विपक्ष का नेता
- कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ओम बिरला 18वीं लोक सभा के स्पीकर
- केरल द्वारा नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग
- कस्टोडियल डेथ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस

न्यायपालिका

- पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया

संस्थान एवं निकाय

- NIIMH को WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया
- एआईएम-आईसीडीके वॉटर चैलेंज 4.0

राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली

नरेन्द्र मोदी : लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री

9 जून, 2024 को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई।

- भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के पश्चात नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए है।
- प्रधानमंत्री के साथ नई गठबंधन सरकार के 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री एवं 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शामिल हैं।
- शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित विदेशी नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हुए।

18वीं लोक सभा चुनाव

- 18वीं लोक सभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून, 2024 के मध्य 7 चरणों में आयोजित हुए, जिसके परिणाम 4 जून, 2024 को घोषित किये गए।
- 2024 के लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को 22 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) को 16 सीटें तथा जनता दल (यूनाइटेड) [JD(U)] को 12 सीटें प्राप्त हुईं।
- 18वीं लोक सभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोक सभा में बहुमत के आंकड़े (272) से काफी ऊपर है।
- 2024 के आम चुनाव में लोक सभा के लिए 74 महिला सांसदों को चुना गया, जो 2019 की तुलना में चार कम और 1952 में भारत के पहले चुनावों की तुलना में 52 अधिक है।
- ये 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% हिस्सा हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 46%, ब्रिटेन में 35% तथा अमेरिका में 29% है।

विशेषाधिकार समिति ने 12 सांसदों को कदाचार का दोषी पाया

27 जून, 2024 को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) ने 12 विपक्षी सांसदों को अगस्त 2023 में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कदाचार का दोषी ठहराया और उन्हें भविष्य में इस तरह के व्यवहार से बचने की चेतावनी दी।

- समिति ने संसद के उच्च सदन में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि **12 सदस्यों को विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन** तथा राज्य सभा की अवमानना का दोषी माना गया है।
- **विशेषाधिकार समिति** संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और समाधान के लिए उत्तरदायी है।
- संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को उनके कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए दिए गए विशेष अधिकार होते हैं।
- **संविधान के अनुच्छेद 105** में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है।
- संसद सदस्यों को कुछ **व्यक्तिगत विशेषाधिकार** (Personal Privilege) और **सामूहिक विशेषाधिकार** (Collective Privilege) प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें।
- लेकिन अगर कोई सदस्य इन विशेषाधिकारों या अधिकारों में से किसी की अवहेलना या दुरुपयोग करता है, तो इसे **विशेषाधिकार हनन** (Breach of the Privilege) माना जाता है।

सार्वजनिक नीति

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के नियम अधिसूचित

हाल ही में, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो 21 जून, 2024 से लागू होंगे।

नियमों के मुख्य बिंदु

- यदि प्रथम दृष्टया सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों या अपराध का मामला सामने आता है, तो **स्थल प्रभारी को FIR दर्ज करने सहित उचित कार्रवाई करने का प्रावधान** है।
- यदि सेवा प्रदाता के **प्रबंधन या निदेशक मंडल की संलिप्तता** हो तो सार्वजनिक जांच प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित करने का प्रावधान है।
- **सेवा प्रदाता** कोई भी एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई आदि है, जिसे सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों या अपराध की सभी घटनाओं की क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकारी को समय-समय पर रिपोर्टिंग की जाएगी तथा साथ ही की गई कार्रवाई का विवरण भी दिया जाएगा।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

- **'अनुचित साधनों'** में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि शामिल हैं।
- अनुचित साधनों का **सहारा लेने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए** कम से कम तीन वर्ष का कारावास, जो पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और दस लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति/समूह के लिए** 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा तथा जांच की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।
- सभी **अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य** होंगे।

फेमा के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव

7 जून, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999' के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा।

- उदारीकरण के बाद के **भारत में बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ, 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम** के रूप में **FEMA 1 जून 2000 को लागू** हुआ था।
- **FEMA का मुख्य उद्देश्य** बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है।
- FEMA भारत में **विदेशी मुद्रा लेनदेन की प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं, व्यवहार** आदि से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
- FEMA **विदेशी मुद्रा लेनदेन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित** करता है, जिसमें विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण और धारण, विदेशी मुद्रा लेनदेन का भुगतान और निपटान, मुद्रा का निर्यात और आयात, तथा अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
- यह **सम्पूर्ण भारत पर लागू** है तथा भारत के बाहर स्थित एजेंसियों और कार्यालयों (जिनका स्वामित्व या प्रबंधन किसी भारतीय नागरिक के पास है) पर भी समान रूप से लागू है।
- **यह अधिनियम RBI को अधिनियम** के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम और विनियम बनाने का भी अधिकार देता है।
  - यह विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराध को भी सिविल अपराध बनाता है। FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- FEMA का **मुख्यालय प्रवर्तन निदेशालय** के नाम से जाना जाता है और यह **दिल्ली में** स्थित है।
  - इसके **दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में 5 क्षेत्रीय कार्यालय** हैं, प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख एक उप निदेशक होता है।
  - प्रत्येक 5 जोन को सहायक निदेशकों की अध्यक्षता में **7 उप-जोनल कार्यालयों और मुख्य प्रवर्तन अधिकारियों की अध्यक्षता में 5 क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित** किया गया है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक

अर्द्धवार्षिक 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (FSR) में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

- यह **अर्द्धवार्षिक 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'** (FSR) **'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद'** की उप-समिति के आकलन पर आधारित है।
- इसमें बताया गया है कि **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए** (GNPA) और शुद्ध एनपीए अनुपात मार्च 2024 के अंत में क्रमशः 2.8% और 0.6% के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर आ गया है।
- **NPA से तात्पर्य** किसी बैंक के उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण से है जो बकाया हैं।
  - जब मूलधन या ब्याज का भुगतान देरी से किया जाता है या नहीं किया जाता है तो ऋण बकाया माना जाता है और जब मूलधन का ब्याज/किस्त **90 दिनों से अधिक** समय तक बकाया रहता है तो ऋण NPA बन जाता है।
  - **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां** (GNPAs) उन सभी ऋण परिसंपत्तियों का योग है जिन्हें NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **NPA के कारणों में** 'जानबूझकर चूक में वृद्धि' (मार्च 2023 तक 353,874 करोड़ रुपये), 'बैंक धोखाधड़ी में वृद्धि' (अप्रैल-सितंबर 2023 के बीच 14,483 मामले, जबकि 2022 की समान अवधि में 5,396 मामले थे) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंकिंग परिचालन के संबंध में विनियामक निर्देशों का अनुपालन न करना शामिल है।
- **NPA को कम करने के लिए उठाए गए कदम**
  - **SARFAESI अधिनियम, 2002:** यह अधिनियम सुरक्षित लेनदारों को पुनर्भुगतान में चूक होने पर संपार्श्विक (Collateral) पर कब्जा करने की अनुमति देता है।
  - **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016:** इसे 180 दिनों (90 दिनों की विस्तारित अवधि) के भीतर कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान के लिए लाया गया था।
  - **नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** का गठन किया गया है जो 500 करोड़ रुपये से अधिक की तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान करेगी।

भारत में वृद्धावस्था की देखभाल चुनौतियों पर रिपोर्ट

15 जून, 2024 को 'विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस' के अवसर पर हेल्पएज इंडिया द्वारा **'भारत में वृद्धावस्था: देखभाल चुनौतियों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज'** (Ageing in India: Exploring Preparedness and Response to Care Challenges) नामक रिपोर्ट जारी की गई है।

- **हेल्पएज इंडिया** (HelpAge India) भारत में एक धर्मनिरपेक्ष, गैर-लाभकारी संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2050 **तक बुजुर्ग जनसंख्या** (60 वर्ष और उससे अधिक) कुल जनसंख्या का 20.8% होगी, जो 2011 में 8.6% थी।
- अध्ययन में पाया गया कि **केवल 15% बुजुर्ग व्यक्ति काम करते** हैं। इनमें 24% वृद्ध पुरुष जबकि 7% वृद्ध महिलाएं शामिल हैं।
- भारत में **अधिकांश वृद्ध लोगों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच का अभाव** है, केवल 29% वृद्ध लोगों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच है।
- सभी वृद्ध व्यक्तियों में से **54% दो या अधिक गैर-संचारी रोगों से पीड़ित** हैं।
- यह पाया गया कि **59% लोगों के पास डिजिटल डिवाइस तक पहुंच नहीं** है।
- वृद्ध जनसंख्या की **सामाजिक भागीदारी न्यूनतम** है, केवल 7% लोग किसी सामाजिक संगठन के सदस्य हैं।

भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए उठाए गए कदम

- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (2015):** 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (2017):** वरिष्ठ नागरिकों (गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी) को सहायक जीवन उपकरण और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना।

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक न्याय

- लिविंग विल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति
- 18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- लिंग-तटस्थ स्कूल पाठ्य पुस्तकें

सामाजिक–आर्थिक विकास

- भारत में 'प्रेस्टन कर्व' पर चर्चा
- कृषि सखियों को प्रमाण-पत्र वितरित

सामाजिक न्याय

लिविंग विल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति एमएस सोनक गोवा में **'लिविंग विल'** (Living Will) पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

- **'लिविंग विल'** एक **अग्रिम चिकित्सा निर्देश** है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि जब पंजीकृत करने वाला व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है तो क्या कार्रवाई करनी होगी।
- दूसरे शब्दों में, **लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज** है जिसमें व्यक्ति अपनी चिकित्सा उपचार संबंधी **प्राथमिकताओं को पहले से ही रेखांकित** करता है, जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब वह अक्षम हो जाए या संवाद करने में असमर्थ हो जाए। यह एक स्वैच्छिक निर्णय है।
- **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनआरआर** (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि लगातार **'सुषुप्त अवस्था'** (Vegetative Stage) में रहने वाला व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जैसे कि जीवन समर्थन वापस लेना) का विकल्प चुन सकता है।
  - **न्यायालय के अनुसार,** लिविंग विल व्यक्तियों को **लाइलाज बीमारी की स्थिति में चिकित्सा उपचार से इनकार करने की अनुमति** देता है।
- **गोवा** इन निर्देशों को औपचारिक रूप से **लागू करने वाला पहला राज्य** है।
- लिविंग विल को **दो गवाहों की उपस्थिति में तैयार** किया जाना चाहिए, किसी **राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित** किया जाना चाहिए तथा उसे **सुरक्षित रखने के लिए जिला कलेक्टर के पास भेजा जाना** चाहिए।

18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

हाल ही में गठित 18वीं लोक सभा में 74 महिलाएं निर्वाचित हुईं, जिनका लोक सभा में 13.6% प्रतिनिधित्व है।

- लोकसभा में **महिलाओं की संख्या 17 वीं लोकसभा की तुलना में कम** है, जब 78 महिलाएं (14.4% प्रतिनिधित्व) निर्वाचित हुई थी।
- **18 वें लोक सभा चुनाव में 797 महिला प्रत्याशियों में से 9.7% विजयी** रहीं, जबकि 17 वें लोकसभा चुनाव में 726 महिला प्रत्याशियों में से 10.74% विजयी रहीं।
- लोकसभा में **महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रथम लोक सभा में 5%** से बढ़कर 17 वीं लोकसभा में अपने उच्चतम स्तर (14.4%) पर पहुंच गया।
- वर्तमान में, **राज्य सभा सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 14.05%** है। विश्व स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 26.9% है।

महिला प्रतिनिधित्व का महत्व

- महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में **आर्थिक संकेतकों पर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेहतर** प्रदर्शन करती हैं।
- लगभग 50% आबादी के लिए **विधायी प्रतिनिधित्व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मौलिक** है।

महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व के मार्ग में चुनौतियां

- सामाजिक पूर्वाग्रह, पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं और पारिवारिक दायित्व।
- चुनाव अभियान महंगे होते हैं, समय लेते हैं और अनुचित टिप्पणियों, घृणास्पद भाषणों, अपमानजनक धमकियों और बाहुबल के कारण खराब हो जाते हैं।

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023** (106वां संशोधन अधिनियम) लोकसभा और दिल्ली विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए लाया गया है।
- **73 वें और 74 वें संविधान संशोधन** द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए **1/3 सीटें आरक्षित** की गई है।
- भारत ने **सतत विकास लक्ष्य 5.5** को प्राप्त करने का संकल्प लिया है, जिसमें राजनीति और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी की बात कही गई है।

कल्याणकारी योजनाएं

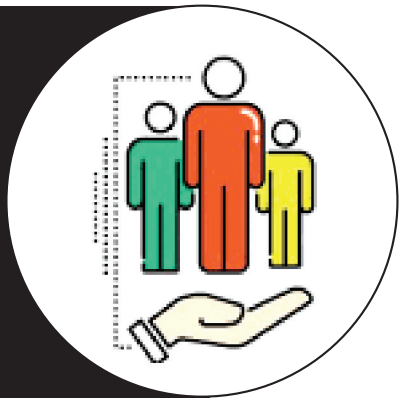

राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना

19 जून, 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना' (NFIES) के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

- **राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना का उद्देश्य** 28 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर से बाहर प्रयोगशालाएं स्थापित करके देश भर में फॉरेंसिक अवसंरचना को बढ़ाना है।
- इस योजना का 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए **कुल वित्तीय परिव्यय 2,254.43 करोड़ रुपये** है।
- इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:
  - देश भर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के परिसरों की स्थापना करना।
  - देश में केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
  - NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **इसका उद्देश्य** प्रशिक्षित फॉरेंसिक जनशक्ति की कमी को दूर करना तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की क्षमता और योग्यता को मजबूत करना है।
- योजना के माध्यम से **देश भर में नई केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना** का उद्देश्य मौजूदा फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों की संख्या को कम किया जाएगा।
- **नए आपराधिक कानून के लागू होने से,** जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है, **फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद** है।
- उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित **फॉरेंसिक पेशेवरों से यह अपेक्षा** की जाती है कि वे प्रौद्योगिकी में प्रगति का लाभ उठाते हुए एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया में योगदान दें।
- इस योजना का उद्देश्य 90% से अधिक की उच्च दोषसिद्धि दर प्राप्त करने के सरकार के उद्देश्य को पूरा करना है।
- **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय** (NFSU) की स्थापना 2009 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के रूप में की गई थी।
- **यह अपनी तरह का दुनिया का पहला और एकमात्र फॉरेंसिक विश्वविद्यालय** है। इसकी स्थापना फॉरेंसिक विज्ञान में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और देश में मांग को पूरा करने के लिए की गई थी
- **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020** द्वारा इसका नाम बदलकर NFSU कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना दिया गया। NFSU **केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन** है तथा इसका **मुख्य परिसर गांधीनगर, गुजरात में** है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

3 जून, 2024 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (NLCC) ने नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में पहली बैठक की।

- समिति ने **11 राज्यों में अपने पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा** की, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बहु-सेवा समितियों में बदलना है।
- इस **योजना का उद्देश्य** कृषि भंडारण अवसंरचना की कमी को दूर करना तथा PACS को खरीद केन्द्रों, उचित मूल्य की दुकानों, कस्टम हायरिंग केन्द्रों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है।
  - इससे खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, मजबूरी में बिक्री पर रोक लगेगी, परिवहन लागत कम होगी और पैक्स को मजबूती मिलेगी।
- पायलट परियोजना को **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** (NCDC) द्वारा नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), नाबार्ड परामर्श सेवाएं (NABCONS) के सहयोग से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय में लागू किया गया है।
  - इसके अलावा, **राज्य सरकारों,** NCCF, **राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम** (NBCC) आदि के सहयोग से 500 अतिरिक्त PACS में पायलट परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों, जैसे राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) ने परियोजना के तहत **भंडारण क्षमता और अन्य कृषि अवसंरचना के निर्माण** के लिए अतिरिक्त PACS की पहचान की है।
- **भारत के पास दुनिया के कुल कृषि योग्य क्षेत्र** (138 करोड़ हेक्टेयर) **का 11%** (16 करोड़ हेक्टेयर) और कुल विश्व जनसंख्या (790 करोड़) का 18% (140 करोड़) है।
  - **इसका अर्थ यह है कि** विश्व की 18% आबादी की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत के पास केवल 11% खेती योग्य भूमि है।

विरासत एवं संस्कृति

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

- संत कबीर दास
- बिरसा मुंडा

कला एवं संस्कृति

- श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा
- भारत का पहला यूनेस्को 'साहित्य का शहर': कोझिकोड
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
- अंबुबाची मेला

स्थापत्य विरासत

- नालंदा विश्वविद्यालय

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

संत कबीर दास

22 जून, 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संत कबीर दास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनकी जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है।

- कबीर के **जन्म** का सटीक विवरण अस्पष्ट है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का अनुमान है कि उनका जन्म 1398 ई. में हुआ था। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था।
- उनका पालन-पोषण वाराणसी शहर या उसके पास बसे मुस्लिम जुलाहा या बुनकरों के परिवार में हुआ था।
- वे 15वीं शताब्दी के **रहस्यवादी कवि, संत एवं समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन** के प्रस्तावक थे। कबीर की विरासत अभी भी 'कबीर पंथ' (एक धार्मिक समुदाय) नामक पंथ के माध्यम से चल रही है।
- भक्ति आंदोलन से प्रभावित, उनकी रचनाओं को 'भजन' और 'दोहा' के रूप में जाना जाता है। वे अपने दो-पंक्ति वाले दोहों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है। कबीर दास की विचारधारा वैष्णव संत स्वामी रामानंद से बहुत प्रभावित थी, जिन्होंने कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था।
- कबीर की कृतियां हिंदी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें समझना आसान था। लोगों को जागरूक करने के लिये वे अपने लेख दोहों के रूप में लिखते थे। उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं।
- उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की 'बाह्य पूजा के सभी रूपों' का खुले तौर पर उपहास किया। कबीर एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति या श्रद्धा है।
- उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण उत्तर प्रदेश के मगहर में व्यतीत किये थे।
- संत कबीर ने समाज को समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाया। उन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन में रहकर भी एक संत की तरह साधारण जीवन व्यतीत किया।
- उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और सहानुभूति में वृद्धि करके असहाय लोगों की सहायता द्वारा समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया था। कबीर दास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा था।
- कबीर दास ने कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ और पंच वाणी जैसे ग्रथों का लेखन कार्य किया था।
- उन्होंने अवधी, ब्रज और भोजपुरी को मिलाकर हिंदी में अपनी कई कविताएं लिखी थीं। कबीर दास की रचनाएं मुख्य रूप से पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित थीं।

बिरसा मुंडा

9 जून, 2024 को क्रांतिकारी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्य तिथि मनाई गई। बिरसा मुंडा देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और श्रद्धेय जनजातीय नायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी।

- इनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के लोहरदगा जिले के उलिहातु गांव (जो वर्तमान में झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है) में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पुर्ती (मुंडा) और माता का नाम करमी पुर्ती (मुंडा) था।
- बिरसा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात इनके पिता ने मिशनरी स्कूल में अच्छी पढ़ाई के लिए भर्ती करा दिया।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों तथा मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के मिशनरियों के प्रयासों के बारे में जानने के पश्चात बिरसा ने 'बिरसैत' (Birsait) की आस्था शुरू की। जल्द ही मुंडा और उरांव समुदाय के सदस्य बिरसैत संप्रदाय में शामिल होने लगे तथा धर्मांतरण गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया।
- बिरसा मुंडा ने आचरण की शुद्धता एवं आत्मसुधार पर बल दिया। उन्होंने जनजातियों को अंधविश्वास की जकड़न से निकालने का भी प्रयास किया। उन्होंने जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

अवसंरचना

- वधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी

उद्योग

- भारतीय उद्योग जगत द्वारा एंजेल टैक्स को हटाने की मांग
- कोलार गोल्ड फील्ड्स में खनन पुनः प्रचालित करने का निर्णय
- फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु रूपरेखा

सेवा क्षेत्र

- 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम'

संसाधन

- 53वीं जीएसटी परिषद बैठक
- राज्यों को कर हस्तांतरण की किस्त जारी

बैंकिंग एवं वित्त

- पंप एंड डंप स्कीम के संचालन को लेकर SEBI ने लगाया जुर्माना
- ऑनलाइन भुगतान धोखाधाड़ी कम करने हेतु ए.पी. होता समिति
- प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा
- आरबीआई द्वारा पर कुछ शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द

विदेशी व्यापार और एफडीआई

- 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएं

- भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि

अवसंरचना

वधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी

19 जून, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन (Vadhavan) में एक प्रमुख पत्तन (Major Port) के निर्माण को मंजूरी दे दी।

- **वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र के पालघर जिले** के वधावन में एक स्वीकृत ग्रीनफील्ड गहरे समुद्र का बंदरगाह है।
- इस बंदरगाह को **सभी मौसमों में उपयोग में आने वाले गहरे ड्राफ्ट वाले प्रमुख बंदरगाह** के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में मुख्य बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा।
- इस परियोजना का **निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड** (VPPL) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% है।
- भूमि अधिग्रहण को मिलाकर इस **परियोजना की कुल अनुमानित लागत 76,220 करोड़ रुपये** है।
- बंदरगाह में **9 कंटेनर टर्मिनल होंगे**, जिनमें से प्रत्येक 1000 मीटर लंबा होगा, तटीय बर्थ सहित चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार तरल कार्गो बर्थ और एक तटरक्षक बर्थ होंगे।
- इस परियोजना में **समुद्र में 1,448 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्ग्रहण तथा 10.14 किलोमीटर अपतटीय ब्रेकवाटर और कंटेनर/कार्गो भंडारण क्षेत्रों का निर्माण** शामिल है।
- इस परियोजना से **प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन** (MMT) की संचयी क्षमता सृजित होगी, जिसमें लगभग 23.2 मिलियन टीईयू (बीस फुट समतुल्य/Twenty Foot Equivalent) कंटेनर हैंडलिंग क्षमता भी शामिल होगी।
- यह परियोजना एक **लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे** (Delhi-Mumbai Expressway) से जुड़ी होगी।
- यह आगामी **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर** (IMEC) और **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर** (INSTC) के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में काम करेगा।
  - यह देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की **सागरमाला पहल के अंतर्गत एक प्रमुख परियोजना** है।

उद्योग

भारतीय उद्योग जगत द्वारा एंजेल टैक्स को हटाने की मांग

हाल ही में, भारतीय उद्योग जगत द्वारा स्टार्टअप फंडिंग में तीव्र गिरावट और रोजगार के नुकसान के बीच एंजेल टैक्स को हटाने का आग्रह किया गया है। वित्त विधेयक 2023 में इसके विस्तार के बाद से यह कर एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

- **भारतीय उद्योग परिसंघ** (CII) ने अपने केंद्रीय बजट सुझावों में **आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(7b)** को खत्म करने की सिफारिश की है, जिसे 'एंजेल टैक्स' के नाम से जाना जाता है। उनका तर्क है कि इस कर को हटाने से देश में पूंजी निर्माण में काफी मदद मिलेगी।
- **एंजेल टैक्स से तात्पर्य** किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है, जो तब लगाया जाता है, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को **उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है।**
- **एंजेल टैक्स पहली बार** 2012 में लागू किया गया था, ताकि किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों को उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदकर बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोका जा सके।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

अंतरराष्ट्रीय संगठन

- 50वां जी7 शिखर सम्मेलन
- आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 2024
- वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी+20 फोरम 2024
- भारत द्वारा कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता

वैश्विक मुद्दे

- यूरोपीय संसद के चुनावों में दक्षिणपंथी दलों का उदय

- पाकिस्तान और चीन CPEC को उन्नत करने पर सहमत

मानचित्र के माध्यम से

- साइपन द्वीप, नैट्रॉन झील, नामक्वालैंड, तेचो फुनान नहर

अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते

- भारत एवं रूस के मध्य 'रसद पारस्परिक आदान-प्रदान समझौता' मसौदा
- सार्क देशों के साथ मुद्रा विनिमय व्यवस्था की रूपरेखा में संशोधन
- श्रीलंका एवं आधिकारिक ऋणदाता समिति के मध्य ऋण समझौता
- स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- ताइवान के विरुद्ध चीन की ग्रे-जोन युद्ध रणनीति

अंतरराष्ट्रीय संगठन

50वां जी7 शिखर सम्मेलन

13-15 जून, 2024 के मध्य इटली के अपुलिया में स्थित फसानो (Fasano) शहर में 50वें G7 शिखर सम्मेलन (50जी G7 Summit) का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली द्वारा की गई। **अगला जी7 शिखर सम्मेलन** वर्ष 2025 में **कनाडा के अल्बर्टा** में होगा।

- 50वें G7 शिखर सम्मेलन में **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भाग लिया** एवं इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया।
- सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 **'अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल'** (AFSI) का शुभारंभ किया गया।
- शिखर सम्मेलन में **'वैश्विक अवसंरचना निवेश'** के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया।
  - यह पहल अमेरिका और जी7 सहयोगियों द्वारा 2022 में **48वें जी7 शिखर सम्मेलन में** शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करना है।
- बैठक में **उन्नत AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता** के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई।
- जी7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने मध्य अफ्रीका में **लोबिटो कॉरिडोर** (अंगोला से जाम्बिया तक), लुजोन कॉरिडोर (फिलीपींस के लूजोन द्वीप पर) और **ट्रांस-कैस्पियन अंतरराष्ट्रीय परिवहन मार्ग के रूप में प्रसिद्ध मिडिल कॉरिडोर** (यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला) के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
- बैठक में सदस्य देशों द्वारा वर्ष **2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- जी7 नेताओं ने 'पश्चिम और शेष' के बीच मतभेदों को पाटने, अफ्रीका में निवेश करने तथा प्रवासन, जलवायु परिवर्तन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न बैठकों में भाग लिया।
- **G7 समूह की स्थापना वर्ष 1975 में** तेल संकट के प्रतिक्रियास्वरूप की गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी (पश्चिम), जापान और इटली नामक 6 देशों ने G7 की स्थापना की थी।
- वर्ष **1976 में कनाडा भी इसमें शामिल** हो गया। यह कहा जा सकता है कि इस समूह के सदस्य विश्व की सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं।
- यद्यपि **भारत जी7 का सदस्य नहीं** है, परन्तु भारत को 'ग्लोबल साउथ' के अग्रणी लीडर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। भारत ने **2023 से 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' सम्मेलन की मेजबानी** की है।
- भारत के लिए, **जी7 आउटरीच सत्र** अपनी उपलब्धियों और दृष्टिकोणों को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
- अब तक **भारत को G7 की बैठकों में 11 बार** आमंत्रित किया गया है और **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवीं बार** इसमें भाग लिया।

आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 2024

6 जून, 2024 को भारत ने सिंगापुर में आयोजित हिन्द-प्रशांत समृद्धि के लिए आर्थिक ढांचे (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसमें हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में की गई महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया गया।

- IPEF सदस्यों ने **स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समग्र IPEF समझौते पर केंद्रित तीन समझौतों** पर हस्ताक्षर किए।

- इस ढांचे के तहत एक **नई रुपया स्वैप विंडो** (New Rupee Swap Window) शुरू की गई है, जो भारतीय रुपये में स्वैप का समर्थन करने के लिए विभिन्न रियायतें प्रदान करती है।
- इस समर्थन के लिए **कुल कोष 25,000 करोड़ रुपये** है। RBI एक अलग **USD/Euro स्वैप विंडो** के माध्यम से अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था की पेशकश जारी रखेगा, जिसमें **कुल कोष 2 बिलियन डॉलर** का होगा।
- **मुद्रा स्वैप समझौता** दो पक्षों के बीच विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज भुगतान का आदान-प्रदान करने हेतु एक वित्तीय अनुबंध है।
- इस तरह के **समझौते का प्राथमिक उद्देश्य** अधिक अनुकूल ऋण शर्तें प्राप्त करना या मुद्रा जोखिम के विरुद्ध बचाव करना है।
- **सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर 2012** को लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य सार्क देशों में अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन के संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित होने तक वित्तपोषण की बैकस्टॉप लाइन (Backstop Line of Financing) उपलब्ध कराना था।
- अब तक **भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 23 देशों के साथ** इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है, जिनके साथ भारत स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर सकता है।
- **'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन'** (SAARC) दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन और भू-राजनीतिक संघ है। इसकी **स्थापना 1985 में ढाका में सार्क चार्टर** पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- **सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू** में की गई थी।
- सार्क में **8 दक्षिण एशियाई देश शामिल** हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका।

श्रीलंका एवं आधिकारिक ऋणदाता समिति के मध्य ऋण समझौता

26 जून, 2024 को श्रीलंका ने फ्रांस के पेरिस में 5.8 बिलियन डॉलर के बकाया ऋण के पुनर्गठन के लिए अपने द्विपक्षीय ऋणदाताओं की आधिकारिक ऋणदाता समिति [Official Creditor Committee (OCC)] के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- श्रीलंका ने चीन के एक्जिम बैंक के साथ भी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये; इस प्रकार श्रीलंका द्वारा कुल 10 अरब डॉलर के अंतिम पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - ये समझौते श्रीलंका की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
- इस कदम से श्रीलंका को **सितंबर 2022 में शुरू की गई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में मदद** मिलेगी।
- इन समझौतों से श्रीलंका को **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ 2.9 बिलियन डॉलर** के बेलआउट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य उसके वित्तीय संकट को समाप्त करना है।
- **OCC में पेरिस क्लब के सदस्य सहित 17 देशों के प्रतिनिधि** शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से श्रीलंका को 5.8 अरब डॉलर का ऋण दिया है तथा इसकी सह-अध्यक्षता जापान, भारत और फ्रांस कर रहे हैं।
- फ्रांस और जापान के साथ ओसीसी के सह-अध्यक्ष के रूप में, भारत श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण, सुधार और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है।
- यह **भारत द्वारा श्रीलंका को** 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अभूतपूर्व **वित्तीय सहायता** से भी प्रदर्शित हुआ।
- भारत, आईएमएफ को वित्तीय आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश भी था, जिसने श्रीलंका के लिए, आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया।
- आधिकारिक ऋणदाता समिति **(OCC)** का **उद्देश्य** 2022 में अभूतपूर्व वित्तीय संकट के मद्देनजर, श्रीलंका द्वारा अपने बाह्य ऋण पर चूक (Default on External Debt) के बाद श्रीलंका के लिए ऋण वार्ता को सरल बनाना था।
- **OCC एक अस्थायी मंच** है, और इसका कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। फ्रांस में पेरिस क्लब का सचिवालय होने के कारण OCC की बैठकें आम तौर पर पेरिस में ही आयोजित की जाती हैं।
- **पेरिस क्लब 1956 में गठित** प्रमुख ऋणदाता देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य उन देशों के लिए स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना है, जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।
- पेरिस क्लब में **22 स्थायी सदस्य देश** शामिल हैं, जो मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया से हैं।

स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों ने 25-28 जून, 2024 के मध्य 'स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों पर समिति' (SPS Committee) की बैठक में 'स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर डब्ल्यूटीओ समझौते' (SPS Agreement) के संचालन और कार्यान्वयन की छठी समीक्षा की प्रगति पर चर्चा की।

- उन्होंने अनेक व्यापार संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा की तथा 13वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (13जी WTO Ministerial Conference) में अपनाए गए घोषणा-पत्र को स्वीकार किया, जिसमें 'एसपीएस समझौते' और 'व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते' में विशेष एवं विभेदकारी उपचार प्रावधानों के कार्यान्वयन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

सतत विकास

- पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र

प्रदूषण

- वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषक में कमी

जलवायु परिवर्तन

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) की 67वीं बैठक
- बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क
- बॉन में सम्मेलन का आयोजन
- हीट डोम
- हिंदू कुश हिमालय हिमपात अपडेट

आपदा प्रबंधन

- भारत के प्रमुख जलाशयों में जल की कमी

जैव विविधता

- स्ट्रिप्ड सीसिलियन : अंगहीन उभयचर की प्रजाति
- नए रामसर स्थल: नागी और नकटी वेटलैंड्स
- उच्च सागर जैव विविधता संधि

सतत विकास

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र

हाल ही में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा द्वारा पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Areas - ESA) की सीमा को कम करने की मांग की गई है ताकि इन राज्यों द्वारा विकास कार्यों को इन क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की जा सके।

- इन राज्यों ने पश्चिमी घाट के **56,825 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में फैले इन पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) प्रस्तावित किए हैं।
- प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे के साथ पश्चिमी घाट में लगभग 77% उभयचरों एवं 62% सरीसृपों की **स्थानिक प्रजातियां** पायी जाती हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट और भारतीय प्रायद्वीप के बीच स्थित हैं।
- पश्चिमी घाट की पवन अभिमुख ढाल मानसून से वर्षा की उच्च मात्रा प्राप्त करती हैं, जिससे यह क्षेत्र जैविक रूप से समृद्ध और भौगोलिक रूप से अद्वितीय बन जाता है। इस क्षेत्र से भीमा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं।
- राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (2006) ने **पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों** को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया है, जिनमें पर्यावरणीय रूप से अतुलनीय मूल्यवान संसाधन होते हैं। इसके साथ ही इनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती हैं।
- पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों को **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,** 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के अनुसार, पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के 10 किमी के भीतर स्थित क्षेत्र होते हैं।
- अगस्त 2012 में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने **के. कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया गया था। इसने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने या विनियमन की सिफारिश की थी।

प्रदूषण

वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन

हाल ही में, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) उत्सर्जक राष्ट्र है। विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) उत्सर्जक राष्ट्र चीन है।

- 2020 में भारत कुल मानव जनित वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 11% के लिए जिम्मेदार था, वहीं चीन 16.7% के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद वैश्विक स्तर पर शीर्ष उत्सर्जक अमेरिका (5.7%), ब्राजील (5.3%) और रूस (4.6%) थे।
- इन उत्सर्जनों का मुख्य स्रोत उर्वरकों का उपयोग है। भारत मे नाइट्रोजन-आधारित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर, अतिरिक्त नाइट्रोजन मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण का कारण भी बनता है। वैश्विक स्तर पर नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है तथा इसका उत्सर्जन 1980 और 2020 के बीच 40% बढ़ा है।
- हालांकि, भारत में **प्रति व्यक्ति उत्सर्जन** (किग्रा नाइट्रस ऑक्साइड/व्यक्ति) चीन (1.3), अमेरिका (1.7), ब्राजील (2.5) और रूस (3.3) जैसे देशों की तुलना में सबसे कम (0.8) है। ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि ने पृथ्वी के औसत सतही तापमान को 1850-1900 के औसत की तुलना में 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है।

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

- हॉकिंग विकिरण से संबंधित अध्ययन
- पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान : पुष्पक
- तृष्णा मिशन
- कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर : प्रवाह

रक्षा–विज्ञान

- अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत
- मीडियम रेंज-माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट

स्वास्थ्य विज्ञान

- **H5N2** बर्ड फ्लू से पहली मानव मृत्यु
- सिकल सेल रोग के दवा हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित

जैव–प्रौद्योगिकी

- फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी

नवीन प्रौद्योगिकी

- पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

हॉकिंग विकिरण से संबंधित अध्ययन

हाल ही में किये गए एक अध्ययन के अनुसार मौजूदा टेलीस्कोपों का प्रयोग कर हॉकिंग विकिरण (Hawking Radiation) का पता लगाया का सकता है। ध्यातव्य है कि हॉकिंग विकिरण को सैद्धांतिक (theoretical) रूप से स्वीकार किया गया है, परंतु कभी भी प्रत्यक्ष रूप से इसका अवलोकन नहीं किया गया है।

- यह अध्ययन arXiv नामक एक वैज्ञानिक प्रीप्रिंट सर्वर में हाल ही में प्रकाशित किया गया।
- हॉकिंग विकिरण से संबन्धित सिद्धांत को **स्टीफन हॉकिंग** द्वारा 1974 में प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन (Event Horizon) के निकट विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ब्लैक होल, हॉकिंग विकिरण को क्वांटम प्रभावों के कारण उत्सर्जित करते हैं।
- स्टीफन हॉकिंग ने अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया था कि 'इवेंट होराइजन' के निकट स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले उप-परमाणु कण युग्मों में एक कण ब्लैक होल से बच कर निकल जाता है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा वाला दूसरा कण उसमें गायब हो जाता है।
- ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने वाले कणों को हॉकिंग विकिरण कहा जाता है।
- हॉकिंग विकिरण एक **महत्वपूर्ण परिघटना** है, क्योंकि यह ब्लैक होल के व्यवहार और स्पेस-टाइम की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यदि हॉकिंग विकिरण की पुष्टि हो जाती है, तो यह सैद्धांतिक भौतिकी (Theoretical Physics) में एक महत्वपूर्ण सफलता होगी।
- ब्लैक होल **स्पेस-टाइम** के वे क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उनके प्रभाव से बच नहीं सकता। ये अंतरिक्ष में ऐसे पिंड हैं, जो इतने घने होते हैं कि वे गहरे गुरुत्वाकर्षण सिंक (Gravity Sinks) का निर्माण करते हैं। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि यह अपने चारों ओर के स्पेस-टाइम को परिवर्तित कर देता है।
- ब्लैक होल विभिन्न **प्रकार** के होते हैं। जहां इंटरमीडिएट ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 100 से 100,000 गुना तक होता है, वहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर अरबों गुना तक होता है।

पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान : पुष्पक

23 जून, 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 'पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान' का लैंडिंग प्रयोग [Reusable Launch Vehicle Landing Experiment (RLV LEX)] सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

- इसरो द्वारा विकसित इस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का नाम **'पुष्पक'** (Pushpak) रखा गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR) में किया गया यह प्रयोग पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का तीसरा और अंतिम लैंडिंग परीक्षण था।
- पुष्पक का विन्यास एक **विमान के समान** हैं। परीक्षण के तहत पुष्पक रॉकेट को भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा ऊंचाई पर ले जाया गया तथा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया।
- पुष्पक यान जड़त्वीय सेंसर, रडार अल्टीमीटर, स्यूडोलाइट सिस्टम के साथ-साथ NaVIC **उपग्रह-आधारित पोजिशनिंग** सिस्टम से युक्त है। इसरो इस परीक्षण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कक्षीय पुनः प्रयोज्य वाहन (Orbital Reusable Vehicle) का विकास कर रहा है।
- पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का **उपयोग** अंतरिक्ष अभियानों के लिये कई बार किया जा सकता है। इस प्रकार यह पारंपरिक रॉकेट की तुलना में अधिक किफायती है। साथ ही अंतरिक्ष कचरे की बढ़ती चुनौती के मद्देनजर यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
- इस वाहन के विकसित हो जाने के पश्चात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रहों की **लागत में कमी** आएगी। इसके साथ ही इसरो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकेगा।
- वर्तमान में, विश्व की विभिन्न **अंतरिक्ष एजेंसियां** पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का उपयोग या विकास कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के **स्पेसएक्स** ने फाल्कन 9 नामक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान विकसित किया है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विशेष-2

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

सतत विकास

सतत विकास लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगतिः आलोचनात्मक मूल्यांकन

सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का एक संग्रह है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हैं। विशाल जनसंख्या वाले विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत इन लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति

- **गरीबी उन्मूलन (SDG 1):** भारत ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी सरकारी योजनाएं, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं, और MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) जैसी सामाजिक सुरक्षा जाल ने गरीबी की दरों में कमी लाने में योगदान दिया है।
- **शून्य भूख (SDG 2):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रयास, जो कम आय वाले परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है, और कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे खाद्य वितरण कार्यक्रमों के लागू होने से भूख में कमी आई है। कुपोषण की व्यापकता 2004-06 में 17.3% से घटकर 2017-19 में 14% हो गई। हालांकि यह सकारात्मक प्रगति है, लेकिन बढ़ती आबादी के लिए निरंतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- **शिक्षा (SDG 4):** भारत ने साक्षरता दर और स्कूल नामांकन बढ़ाने में प्रगति की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की है। हालांकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट दरों को कम करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। सीखने की खाई को पाटना और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करना महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **लैंगिक समानता (SDG 5):** स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) ऋण जैसी महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं प्रगति को दर्शाती हैं। फिर भी, लिंग आधारित हिंसा और शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक असमान पहुंच के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।
  - इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है।
- **स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG 6):** स्वच्छ भारत अभियान (**"स्वच्छ भारत मिशन"**) जैसी पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में सुधार किया है। हालांकि, स्वच्छ पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। जल स्रोतों के प्रदूषण और अपर्याप्त जल उपचार बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण निवेश और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है।
- **सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7):** अक्षय ऊर्जा पर भारत का ध्यान प्रगति दर्शाता है। देश सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता बन गया है। हालांकि, जीवाश्म ईंधन पर एक महत्वपूर्ण निर्भरता बनी हुई है, जो पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती है। पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाकर और कोयले पर निर्भरता से दूर होकर एक स्थायी ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करना, इस एसडीजी को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियां और सुधार के क्षेत्र

- यद्यपि भारत ने अनेक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर स्पष्ट प्रगति की है, फिर भी चुनौतियां और सुधार के क्षेत्र अभी भी बने हुए हैं।
- **असमानता:** गरीबी में कमी के बावजूद, आय असमानता उच्च बनी हुई है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस खाई को पाटने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कौशल और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाएं, प्रगतिशील कराधान नीतियों के साथ मिलकर, समान विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा:** आयुष्मान भारत जैसी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच और सामर्थ्य अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, कुपोषण और तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना, निवारक स्वास्थ्य सेवा उपायों को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन (SDG 13):** भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है, जो समुद्र के बढ़ते स्तर, चरम मौसम की घटनाओं और पानी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा विशेष-2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

उभरती प्रौद्योगिकी

भारत में एआई गवर्नेंसः आवश्यकता, चुनौतियां और अनिवार्यताएं

भारत, तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नवाचार का केंद्र बन रहा है। इसके साथ ही एआई समाज के प्रत्येक स्तर को प्रभावित कर रहा है।

- इसके बढ़ते प्रयोग के साथ ही भारत में AI गवर्नेंस (AI Governance) तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा हैं। इस कारण एआई को विनियमित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- मार्च 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा एक एआई एडवाइजरी जारी की गई।
- यह AI मॉडल की समय से पहले तैनाती, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और डीपफेक के प्रसार को रोकने आदि से संबंधित था।

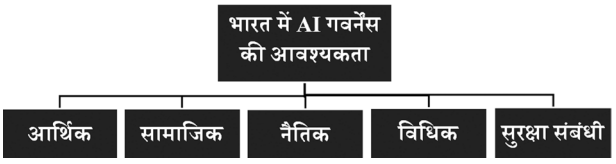

भारत में AI गवर्नेंस की आवश्यकता

- **आर्थिकः** AI के माध्यम से भारत के सकल घरेलू उत्पाद को तेज गति से बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रभावी AI गवर्नेंस सतत विकास और समान लाभ सुनिश्चित कर सकता है।
- **सामाजिकः** AI के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जा सकता हैं। समाज के सभी वर्गों तक इसके लाभ की पहुंच को सुनिश्चित करने में प्रभावी प्रशासन की आवश्यकता है।
- **नैतिकः** वैश्विक स्तर पर AI सिस्टम के प्रयोग से स्पस्ट हुआ है की इनके अल्गोरिदम पूर्वाग्रह, भेदभाव आदि से ग्रस्त हो सकते हैं।
  - इस समस्या के समाधान के लिए AI गवर्नेंस की आवश्यकता है।
- **विधिकः** AI सिस्टम का प्रयोग कर गोपनीयता उल्लंघन, सिस्टम ब्रीच जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए शासन का मजबूत ढांचा आवश्यक हैं।
- **सुरक्षा संबंधीः** जैसे-जैसे AI प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) के साथ एकीकृत होती जा रही हैं, दुर्भावनापूर्ण हमलों के विरुद्ध उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है।

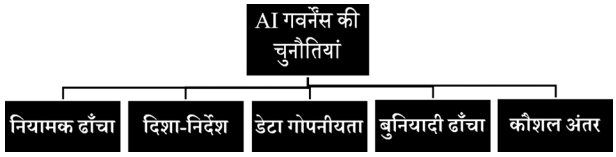

एआई गवर्नेंस की चुनौतियां

- **नियामक ढांचाः** भारत में एआई के लिए व्यापक और स्पष्ट नियामक दिशा-निर्देशों का अभाव है। मौजूदा कानून अक्सर एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपर्याप्त होते हैं।
- **दिशा-निर्देशः** देश में इस प्रकार के दिशा-निर्देश का अभाव है जो एआई के एल्गोरिदम से संबंधित किसी भी गलती के लिए उस संस्था को जवाबदेही बनाया जा सके जो इसके विकास के लिए जिम्मेदार हैं।
- **डेटा गोपनीयताः** एआई सिस्टम का प्रयोग बढ़ने के साथ ही इसके द्वारा उत्पन्न और उपयोग किए जाने वाले डेटा की मात्रा और विविधता बढ़ती जा रही है। इस डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
- **बुनियादी ढांचाः** भारत में इस प्रकार के डिजिटल बुनियादी ढांचे का अभाव है जो एआई के व्यापक पैमाने पर प्रयोग का समर्थन करता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।
- **कौशल अंतरः** एआई प्रौद्योगिकियों में निपुण कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। इस कौशल अंतर को पाटने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

एआई गवर्नेंस के लिए अनिवार्यताएं (Imperatives)

इन चुनौतियों का समाधान करने और एआई की क्षमता का लाभ उठाने के लिए, भारत को कई प्रमुख अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिएः

- **नीति और विनियमनः** व्यापक एआई नीतियां और विनियामक ढांचे विकसित किया जाना चाहिए जो नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रभावों को संबोधित करते हों। इन्हें इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि ये तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रख सके।
- **नैतिकता और निष्पक्षताः** एआई विकास और तैनाती (deployment) के लिए नैतिक दिशा-निर्देश और मानक स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये दिशा-निर्देश निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दें।
- **डेटा गवर्नेंसः** डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने वाले मजबूत डेटा गवर्नेंस ढांचे को लागू किया जाना चाहिए। इसमें डेटा सुरक्षा कानून बनाना और लागू करना शामिल है।

राज्य परिदृश्य

इसके अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों, राज्य स्तर पर आयोजित बैठक एवं सम्मेलनों, सरकारों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश

वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन

18 जून, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 'किसान सम्मान सम्मेलन' को संबोधित किया।

- यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर एवं लगभग 1,00,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
- इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्य मंत्री शामिल हुए।
- इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 17वीं किस्त जारी की।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

- पीएम-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुई।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

5 जिले 100 प्रतिशत 'कैच द रेन' लक्ष्य हासिल करने में सफल

राज्य सरकार के 'कैच द रेन' अभियान के तहत पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और गोंडा ने सरकारी और अर्ध-सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'कैच द रेन' अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी।
- यह पहल पारंपरिक जल निकायों और छोटी नदियों के पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास तथा वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देती है।
- सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि अमृत सरोवरों के जल प्रवाह में गाद और किसी भी अन्य अवरोध को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं।
- अमृत सरोवरों के रखरखाव में गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़ और बाराबंकी शीर्ष पर हैं, जिन्होंने सरोवरों में गाद निकालने और वनस्पति को साफ करने के साथ-साथ सभी सरोवरों का निर्माण भी पूरा कर लिया है।

मध्य प्रदेश

पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ

13 जून, 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 'पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा' (PM Shri Tourism Air Service) का शुभारंभ किया।

- मुख्यमंत्री ने राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया।
- पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश में पर्यटन के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी लाभ होगा।
- इसके अंतर्गत राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा।

बिहार

उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द किया

20 जून, 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

- हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं।
- 27 नवंबर, 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

लघु संचिका

प्रायः सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में नियुक्ति, निधन, पुरस्कारों, चर्चित पुस्तकों, दिवसों आदि से काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए संक्षिप्त स्वरूप में समसामयिक घटनाक्रमों का कवरेज पर्याप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर हम इस खंड में अति संक्षिप्त रूप में इन समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण करते हैं।

चर्चित व्यक्तित्व/ नियुक्ति

सिद्धेश साकोरे

17 जून, 2024 को महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरे को 'मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCCD) द्वारा 'भूमि नायक' (Land Hero) नामित किया गया है।

- विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के अवसर पर UNCCD ने जर्मनी के बॉन में आयोजित कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों के नामों की घोषणा की।
- सिद्धेश साकोरे ने विज्ञान आश्रम नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के लिए प्रशिक्षु के रूप में काम किया और पुणे शहर, महाराष्ट्र के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के इर्द-गिर्द एक मापनीय परियोजना विकसित की।
- उन्होंने मिट्टी के क्षरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए छोटे और हाशिए पर पड़े किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से AGRO RANGERS की स्थापना की।

प्रदीप सिंह खरोलाः NTA के प्रमुख नियुक्त

22 जून, 2024 को प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का महानिदेशक नियुक्त किया गया।

- वे कर्नाटक के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
- वे 2012-13 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे।
- वे एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।
- उन्होंने बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRC) के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है।
- वे शहरी शासन, सार्वजनिक परिवहन और नीति-निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।

अनामिका बी. राजीव

7 जून, 2024 को सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी. राजीव 'भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट' बनीं।

- तमिलनाडु में रानीपेट जिले के अरक्कोणम में स्थित नौसेना वायु स्टेशन 'आईएनएस राजली' में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि अर्जित की।
- अनामिका बी राजीव को पासिंग-आउट परेड में 'गोल्डन विंग्स' प्रदान किया गया।
- नौसेना के पास पहले से ही डॉर्नियर-228 समुद्री गश्ती विमान उड़ाने वाली महिला पायलट हैं, परन्तु सब-लेफ्टिनेंट अनामिका बी. राजीव नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में प्रवेश पाने वाली पहली महिला हैं।
- भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में चेतक, सी किंग्स, ध्रुव और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

निधन

ए.जे.टी. जॉनसिंह

7 जून, 2024 को प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव जैव-वैज्ञानिक 'असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंह' (AJT Johnsingh) का 78 वर्ष की आयु में कर्नाटक के बेंगलुरु में निधन हो गया।

- इनका जन्म 14 अक्टूबर, 1945 को भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में हुआ था।
- जॉनसिंह ने 1970 के दशक की शुरुआत में शिवकाशी में एक प्राणीशास्त्र व्याख्याता के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया।
- 1980 के दशक की शुरुआत में हाथियों पर उनके अग्रणी कार्य ने भारत सरकार को प्रोजेक्ट एलीफेंट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में दुनिया भर के हाथी विशेषज्ञों को लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया।
- भारतीय वन्यजीवन के प्रति आजीवन समर्पण के लिए उन्हें 2004 में कार्ल जीस वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार मिला।
- 2005 में, जॉनसिंह को एबीएन एमरो अभयारण्य लाइफटाइम वन्यजीव सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार एवं सम्मान

18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

- 15-21 जून, 2024 के मध्य महाराष्ट्र के मुंबई में 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (MIFF) 2024 का आयोजन किया गया।
- इस साल के महोत्सव में पहली बार डॉक फिल्म बाजार की शुरुआत की गई, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए उनकी परियोजनाओं हेतु खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक समर्पित बाजार है।

खेल परिदृश्य

खेल जगत में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित

चर्चित खेल व्यक्तित्व

विराट कोहली

29 जून, 2024 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की।

- विराट कोहली ने अपना पहला टी20 मैच 2010 में खेला था।
- कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि अब अगली पीढ़ी को कमान संभालने का समय आ गया है।
- कोहली ने अपने T20 कॅरियर में 4112 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 37 अर्द्धशतक शामिल हैं।

श्रीजा अकुला

हाल ही में, श्रीजा अकुला WTT (विश्व टेबल टेनिस) कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई।

- श्रीजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 इवेंट में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीता।
- श्रीजा अकुला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वह दो बार की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन हैं।
- वह वर्तमान में महिला एकल में भारत की नंबर एक रैंकिंग पर हैं।
- अकुला को 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला।

क्रिकेट

भारत ने दूसरी बार ICC T-20 विश्व कप खिताब जीता

29 जून, 2024 को ICC पुरुष T-20 विश्व कप 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता।

- T-20 विश्व कप का निर्णायक मुकाबला वेस्टइंडीज के केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन मैदान में खेला गया।
- विराट कोहली को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच जबकि जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
- इस जीत के साथ, भारत ICC पुरुष T20 विश्व कप दो बार जीतने वाली तीसरी टीम बन गई, इंग्लैंड (2010, 2022) और वेस्टइंडीज (2012, 2016) यह उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र अन्य टीमें हैं।
- T-20 विश्व कप के 9वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला ICC विश्व कप टूर्नामेंट था।
- T-20 विश्व कप पहली बार 2007 में खेला गया था।

शतरंज

नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट

27 मई से 7 जून, 2024 के मध्य नॉर्वे के स्टावेंजर सिटी (Stavanger City) में 'नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट' का आयोजन किया गया।

- टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में नार्वे के मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फैबियानो कारुआना (Fabiano Caruana) को हराकर छठी बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीता
- महिला वर्ग में चीन की जू वेनजुन (Ju Wenjun) ने चीन के ही लेई टिंगजी (Lei Tingjie) को हराकर खिताब जीता
- मैग्नस कार्लसन जुलाई 2011 से 2830 की लाइव रेटिंग के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं।
- वे क्लासिकल शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन, पांच बार के विश्व रैपिड चैंपियन तथा सात बार के विश्व ब्लिट्ज चैंपियन हैं।
- जू वेनजुन 2558 की लाइव रेटिंग के साथ विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी और चार बार की महिला विश्व चैंपियन हैं।

बैडमिंटन

ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024

11 से 16 जून, 2024 के मध्य ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर में किया गया।

- ऑस्ट्रेलियन ओपन को प्रायोजन कारणों से आधिकारिक तौर पर सैथियो ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 (SATHIO GROUP AUSTRALIAN OPEN 2024) के रूप में जाना जाता है।
- बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सुपर 500 स्तर पर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेताओं की सूची विजेता

खिताब	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	ली जी जिया (मलेशिया)	कोडाई नाराओका (जापान)
महिला एकल	अया ओहोरी (जापान)	एस्टर नूरुमी त्रि वार्डोयो (इंडोनेशिया)
पुरुष युगल	हे जिटिंग एवं मोहम्मद अहसान	चुंग होन जियान एवं चेन जी रे
महिला युगल	फेब्रियाना द्विपुज कुसुमा एवं लाई पेई जिंग	सेत्याना मापासा एवं येउंग नगा टिंग
मिश्रित युगल	जियांग जेन एवं गुओ शिन वा	तांग चुन एवं टैन कियान मेंग

पत्रिका सार

इस खंड में हम भारत सरकार द्वारा जून 2024 में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की परीक्षोपयोगी तथ्यों का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अभ्यर्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

योजना (जून 2024)

भारतीय इतिहास : किलों का महत्त्व

'किला' शब्द आमतौर पर एक मजबूत सुरक्षात्मक इमारत या दीवार अथवा बाड़ वाला स्थान माना जाता है। इसकी **सुरक्षा खाई या गढ़ वाली दीवारों** की अग्रिम पंक्तियों द्वारा अथवा योद्धाओं द्वारा की जाती थी।

- भारत में किलों के **प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य** प्रोटो-ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 3000 और 1500 ईसा-पूर्व के मध्य के हैं।
- **हड़प्पा कालीन सभी बड़े स्थलों** के निर्माण में पक्की एवं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रमुख स्थलों को **सुरक्षात्मक दीवारों** से घेरा जाता था।
- सेल्यूकस निकेटर के **यूनानी राजदूत मेगस्थनीज** के अनुसार 321 ईसा पूर्व में **चंद्रगुप्त मौर्य** की राजधानी पाटिलपुत्र को लकड़ी की दीवारों के साथ एक खाई द्वारा संरक्षित किया गया था।
- **तीसरी शताब्दी में कौटिल्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' में 6 प्रकार** के किलो को संदर्भित किया गया है। इनमें जल-दुर्ग, धन्वन (रेगिस्तानी किला), गिरी-दुर्ग (पहाड़ी किला), वन-दुर्ग, मही-दुर्ग (मिट्टी का किला) तथा नृ-दुर्ग (मानव किला) शामिल हैं।
- **10वीं-11वीं शताब्दी** के बाद राज्यों की राजधानी के रूप में रक्षात्मक किलो का निर्माण किया गया। दिल्ली, आगरा, लाहौर, ओरछा और पुणे इसके उदाहरण है। इन्हें **दुर्ग-किलों** के रूप में विकसित किया गया था, जिनके चारों ओर शहर और कस्बे विकसित हुए।
- **सल्तनत किलो** में दक्कन क्षेत्र में स्थित गुलबर्गा (14वीं शताब्दी), बीदर और बीजापुर (15वीं शताब्दी) तथा गोलकोंडा (16वीं शताब्दी) इस्लामी सल्तनत किलों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
- **यूरोपीय और औपनिवेशिक किलो** में दमन, दीव, सूरत, बॉम्बे, गोवा, हुगली, फोर्ट विलियम, चंद्रनगर, विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में भारतीय उप-महाद्वीप में लगभग **7000 औपचारिक रूप से प्रलेखित और सूचीबद्ध किले** हैं।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किलों का रक्षात्मक वास्तुशिल्प

आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में किलो के निर्माण का आरंभ **मध्ययुगीन काल के आरंभिक वर्षों** से हुआ है। यहां के मुख्य किले **पत्थरों की सहायता** से निर्मित किए गए थे।

- **आंध्र प्रदेश** के प्रमुख किलों में कोंडपल्ली, कोंडाविदु, बेल्लमकोंडा, नागार्जुनकोंडा, विनुकोंडा, उदयगिरि, अडोनी, पुनुकोंडा, रत्नागिरी तथा राय दुर्गम फोर्ट आदि शामिल हैं।
- **तेलंगाना** में मुख्य रूप से निर्मल फोर्ट, बोधन फोर्ट, कॉलेस फोर्ट, खम्मम फोर्ट, रामगिरी फोर्ट, मेदक फोर्ट, कोलिकोण्डा, वारंगल, गोलकुंडा आदि किले ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- आंध्र प्रदेश के **एनटीआर जिले में स्थित कोंडपल्ली किला** सारसेनिक अथवा गोथिक या नवमुगल शैली में निर्मित है।
- आंध्र प्रदेश के **बापटला और पलनाडु जिले में स्थित कोंडाविदु और अद्दांकी** किलो की रक्षा प्राचीर पत्थर की दोहरी परत से निर्मित की गई है।
- **गुटी किला** आंध्र प्रदेश के **आनंदपुर जिले** में स्थित है। **इसमें एक के भीतर एक साथ दुर्ग हैं** तथा 14 प्रवेश द्वार हैं।
- **पेनुगोंडा फोर्ट** आंध्र प्रदेश के **सत्य साईं जिले** में स्थित है। यहां की वास्तुकला हंपी और चंद्रगिरी किलो की भांति है।
- **चंद्रगिरी किला** आंध्र प्रदेश के **तिरुपति जिले** में जबकि **गंडिकोटा किला वाईएसआर कडपा जिले** में है।
- तेलंगाना के **वारंगल जिले में 'वारंगल किला'** स्थित है जिसे काकतीय परंपरा का गौरवपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसके भीतरी दुर्ग का निर्माण विशाल शिलाखंड से किया गया है।
- **कोइलकोंडा किला** तेलंगाना के **महबूबनगर जिले** में है। यह विजयनगर और कुतुबशाही साम्राज्यों का सीमावर्ती किला था।
- **एलगंडल किला** तेलंगाना के **करीमनगर जिले** में है, इसे बेलुगुंडल भी कहते हैं। इसका निर्माण काकतीय शासन काल में हुआ था तथा मुसुनूरी नायकों के शासन के दौरान इसकी गिनती सुदृढ़ किलों में होती थी।

गोलकोंडा किला : एक अभेद्य किला

मोहम्मद कुली कुतुबशाह को दक्कनी साहित्य के साथ तेलुगु साहित्य का भी प्रणेता एवं संरक्षक माना जाता है। इनके द्वारा **हैदराबाद की स्थापना तथा चारमीनार का निर्माण** कराया गया था।

- हैदराबाद के एक शासक **अबुल हसन तानाशाह द्वारा** एक विशिष्ट प्रकार के नृत्य-नाटक का समर्थन किया गया था, जिसे बाद में **कुचिपुड़ी नृत्य** के रूप में लोकप्रियता हासिल हुई।
- **कोह-ए-नूर हीरे** की खोज सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान कृष्णा नदी के तट पर स्थित **कोलार** में हुई थी।

चर्चित शब्दावली

विगत कुछ वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में चर्चित शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। परीक्षा की इसी मांग के अनुरूप समसामयिक सन्दर्भ में चर्चा में रही शब्दावलियों के विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर ही हम यह खंड प्रस्तुत कर रहे हैं।

स्ट्रोमेटोलाइट्स

हाल ही में, किए गए एक अध्ययन में सऊदी अरब के लाल सागर में शेबराह द्वीप पर जीवित उथले-समुद्री स्ट्रोमेटोलाइट्स पाए गए है।

- स्ट्रोमेटोलाइट्स परतदार तलछटी संरचनाएं (माइक्रोबियलाइट) हैं जो मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाई जाती हैं। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए भी आंशिक रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं।

जाइलिटोल

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है जाइलिटोल (Xylitol) दिल के दौरे सहित विभिन्न हृदय संबंधी समस्याओं से जुड़ा हुआ है।

- जाइलिटोल लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है जो विभिन्न प्रकार से पौधों में प्रकृतिक रूप से पाया जाता हैं। इसका स्वाद मीठा होता है और इसे अक्सर चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- जाइलिटोल एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो पानी में घुलनशील होता है। कृत्रिम स्वीटनर का इस्तेमाल आमतौर पर टूथपेस्ट और शुगर-फ्री च्युइंग गम बनाने में किया जाता है।

एंटरोबैक्टर बुगंडेंसिस

हाल ही में, आईआईटी मद्रास और नासा द्वारा किए गए एक अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर एंटरोबैक्टर बुगंडेंसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की गई है।

- इस बैक्टीरिया में मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट पाया गया है जो शून्य गुरुत्वाकर्षण और बढ़े हुए विकिरण जैसी अंतरिक्ष की अनोखी स्थितियों में जीवित रह सकता है।
- मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म (MDRO) ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है।

सफेद फॉस्फोरस

हाल ही में, लेबनान ने इजराइल पर अपने सैन्य अभियानों के दौरान दक्षिणी लेबनान में सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

- सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक (Pyrophoric) है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है, जिससे गाढ़ा, हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस का तीव्र ताप उत्पन्न होता है।
- रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग की वैश्विक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के तहत, सफेद फास्फोरस 'पाइरोफोरिक ठोस-श्रेणी 1' के अंतर्गत आता है।
- इस श्रेणी में वे रसायन शामिल हैं जो हवा के संपर्क में आने पर स्वत: आग पकड़ लेते हैं। सफेद फास्फोरस से लहसुन जैसी विशिष्ट गंध निकलती है।

कैटला

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कैटला 2022 में मनुष्यों द्वारा पकड़े गए जलीय जानवरों की शीर्ष 10 प्रजातियों में से एक था।

- कैटला एक गैर-शिकारी मछली है और यह भोजन के लिए सतह और मध्य-जल के क्षेत्र तक ही सीमित रहती है।
- कैटला का प्राकृतिक वितरण अक्षांश और देशांतर के बजाय तापमान निर्भरता द्वारा नियंत्रित होता है।
- यह 25-32 डिग्री सेल्सियस के बीच के पानी के तापमान पर सबसे अच्छी तरह से वृद्धि करती है।

ट्रूनेट प्लेटफॉर्म

हाल ही में, जिनेवा में सम्पन्न 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में टीबी से निपटने में अपनी सफलता के लिए ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की सराहना की गई।

- ट्रूनेट प्लेटफॉर्म गोवा स्थित मोलबायो डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे आणविक निदान (Molecular Diagnostics) के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व नवाचार माना जा रहा है।
- यह कोविड-19, एचसीवी, एचबीवी, एचआईवी, एचपीवी, डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लूएंजा, हर्पीज, टाइफाइड और टीबी सहित 40 से अधिक बीमारियों का परीक्षण कर सकती है।

संवेदी तंत्रिका संबंधी बहरापन

हाल ही में, गायिका अलका याग्निक को संवेदी श्रवण हानि (Sensorineural Hearing Loss) से प्रभावित पाया गया है।

- संवेदी श्रवण हानि वायरल संक्रमण के कारण होने वाली एक दुर्लभ श्रवण हानि है। यह सुनने में अक्षमता का एक सामान्य प्रकार है। यह श्रवण क्षमता हानि है जो आमतौर पर अचानक एक कान में होती है।
- यह रोग आंतरिक कान की संरचनाओं या श्रवण तंत्रिका को नुकसान के परिणामस्वरूप होता है। तेज आवाजों के लंबे समय तक संपर्क में रहना इसका सर्वाधिक सामान्य कारक है। ■■

संसद प्रश्नोत्तरी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

महिला वैज्ञानिक योजना

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 'विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए किरण' (WISE-KIRAN) योजना के लिए बजटीय आवंटन कितना है? - **131.20 करोड़ रुपये**
- महिला वैज्ञानिक योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में कितने बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों को 1.93 करोड़ रुपये की सहायता से लाभान्वित किया गया है? - **13**
- विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण पहल का उद्देश्य क्या है? - **लिंग-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना**
- WISE-KIRAN के तहत प्रमुख पहल कौन-कौन सी है? - **पीएचडी के लिए WISE फेलोशिप (WISE-PhD), WISE पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप (WISE-PDF) आदि**

पंचायती राज एवं ई शासन व्यवस्था

- जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड़ प्रोजेक्ट के तहत किस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? - **ऑडिटऑनलाइन**
- 24 अप्रैल, 2020 को ई-पंचायत ई-पंचायत मिशन मोड़ प्रोजेक्ट के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है? - **ई-ग्राम स्वराज्य**
- डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से किस परियोजना को कार्यान्वित की जा रही है? - **भारतनेट परियोजना**
- पंचायती राज मंत्रालय ने कितनी सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा तैयार किया है, जो पंचायतों को अपनाने और अनुकूलित करने के लिए स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ मेल खाता है? - **29 क्षेत्रों में**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

- केंद्र सरकार देश भर में आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को कब तक नियुक्त करेगी? - **3 वर्षों में**
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत किस वर्ष शुरू किया गया? - **वर्ष 1997-98**
- भारत के संविधान के किस अनुच्छेद तहत प्राप्त अनुदान से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं? - **अनुच्छेद 275(1)**
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मई, 2021 में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) और आश्रम स्कूलों जैसे जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन में मदद मिल सके? - **माइक्रोसॉफ्ट**

नवचेतना प्रशिक्षण

- 23 नवंबर, 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं एवं छात्रों के मध्य नशामुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? - **इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस (दिल्ली)**
- "नशा मुक्त भारत अभियान" के तहत, स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच जीवन कौशल और नशीली दवाओं पर जागरूकता एवं ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षकों द्वारा किसका प्रसार व कार्यान्वयन किया जा रहा है? - **नवचेतना प्रशिक्षण पैकेज**
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आगामी वर्षों में चुने गए कितने जिलों से चिन्हित विद्यालयों में नवचेतना मॉड्यूल शुरू करने का लक्ष्य रखा है? - **300 जिलों**

'नमो ड्रोन दीदी'

- हाल ही में सरकार ने 1261 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ महिला स्व- सहायता समूह (SHG) को ड्रोन प्रदान करने के लिए किस स्कीम को मंजूरी दी है? - **नमो ड्रोन दीदी'**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की? - **11 मार्च, 2024**
- 'नमो ड्रोन दीदी' स्कीम के माध्यम से कितने चयनित महिला स्व- सहायता समूह द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएं प्रदान की जाएगी? - **15000**

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

- दिसंबर, 2023 के लिए राज्यों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की मासिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? - **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)**
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक के साथ पहले स्थान पर रखा गया है? - **सहकारिता मंत्रालय**
- भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली तथा स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में किसने मान्यता दी है? - **राष्ट्रमंडल सचिवालय**

समसामयिक प्रश्न

जून 2024 के घटनाक्रम पर आधारित

1. नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 5 जून, 2024 को बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया।
2. ये पक्षी अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमि स्थल हैं।
3. नागी पक्षी अभयारण्य को बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।
2. इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई है।
3. 1293 ई. में इसे तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
4. नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) कथन 1 और 3 (b) कथन 1, 2 और 4
(c) कथन 2, 3 और 4 (d) कथन 1, 2, 3 और 4

3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2. वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शुरूआत की थी।
3. नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. डाकघर अधिनियम 2023 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 18 जून, 2024 से डाकघर अधिनियम 2023 लागू हो गया।
2. दिसंबर, 2023 में राष्ट्रपति द्वारा "डाकघर अधिनियम, 2023" को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
3. यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को प्रतिस्थापित करता है।
4. डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अनधिकृत रूप से खोलने पर दंड का उल्लेख है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में कौन सा/से विकल्प सही है?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी।

5. पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कथन (A)- गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए "प्रथम रैंक" का पुरस्कार मिला।
2. कारण (R)- मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(d) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

6. केरल के कोझिकोड के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जून 2024 में, कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को 'साहित्य का शहर' घोषित किया गया।
2. अक्टूबर 2023 में, कोझिकोड को "मूर्तियों का शहर" (शिल्प नगरम) का टैग दिया गया था।
3. जून 2012 में, कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की 'साहित्य' श्रेणी में जगह मिली थी।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

7. भारतीय रेलवे ने जम्मू-कश्मीर में किस नदी पर बनें विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन किया?

(a) झेलम नदी (b) सिंधु नदी
(c) चिनाब नदी (d) व्यास नदी

8. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 'कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024' जारी की गई।

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

सरकारी समाचार सेवाओं-PIB, AIR इत्यादि से संकलित

राष्ट्रीय परिदृश्य

- 18 जून, 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान 'साइबरस्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत' जारी किया?
  - **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने**
- हाल ही में, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने देश में वित्तीय क्षेत्र के साइबर-लचीलेपन को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? - **मास्टरकार्ड इंडिया**
- 17 जून, 2024 को सतत विकास रिपोर्ट (SDR) का 9वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया?
  - **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क**
- 16 जून, 2024 को किसे लंदन स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा "रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024" से सम्मानित किया गया है? - **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को**
- 15 जून, 2024 को किस मंत्रालय ने 'वैश्विक पवन दिवस' का आयोजन किया? - **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**
- 13-14 जून, 2024 के मध्य 'भारत-IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन' कहां आयोजित किया गया? - **नई दिल्ली में**
- 13 जून, 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए लिए पुनर्नियुक्त किया गया? - **अजीत डोभाल को**
- हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप 'एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज' (NCRB Sankalan of Criminal Laws) लॉन्च किया? - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो**
- 13 जून, 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? - **संसद टीवी**
- ब्रिटेन की किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? - **ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी**
- 11 जून, 2024 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने किसे महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? - **ज्योति विज**
- 9 जून, 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई? - **नरेंद्र मोदी**
- 7 जून, 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकथॉन 'HaRBInger 2024 - इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' शुरू किया?
  - **भारतीय रिजर्व बैंक**
- 29 मई, 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहां 'कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट: नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स' सम्मेलन का आयोजन किया गया? - **नई दिल्ली में**
- 28 मई, 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया? - **"प्रगति- 2024"**
- 8 जून, 2024 को किसने मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर यूएवी/यूएएस/ड्रोन एक्सेलेरेशन एंड नेटवर्किंग (UDAAN) कार्यक्रम शुरू किया है?
  - **स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC)**
- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म 'राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय' (Rashtriya e-Pustakalaya) के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून, 2024 को किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये? - **नेशनल बुक ट्रस्ट**

आर्थिक परिदृश्य

- 19 जून, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी? - **14**
- 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नये "SME डिजिटल बिजनेस लोन" उत्पाद का शुभारंभ किया?
  - **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने**
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने हाल ही में किस कंपनी को TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कुछ इक्विटी की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी? - **मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन**
- हाल ही में किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 'नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट' के लोगो का अनावरण किया? - **NHAI**
- हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ब्लैकरॉक फंडिंग, इंक. द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की?
  - **ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, LLC**
- हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में 'बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर' पुरस्कार प्रदान किया गया?
  - **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को**
- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है? - **70 प्रतिशत**